मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

बांगला देश जाते हैं पन्द्रह लाख पशु 3
साफ़ दिखती मोदी की पराजय 4
राफेल में फंसी मोदी सरकार 5
रोजगार पर दगाबाजी 6
थाना-कचहरी नहीं जाऊंगी 8

वर्ष 32 | अंक -22 | फ़रीदाबाद | 14-20 अप्रैल 2019 | फोन - 9999595632 | 2.₹)

हरियाणा चुनाव रिपोर्ट

खट्टर और अभय चौटाला में राजनीतिक खिचड़ी

भाजपा जाट वोटों का बंटवारा कराने के लिए हर दांव खेल रही है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : हरियाणा में राजनीतिक दल जिस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति दिनोंदिन मजबूती की तरफ बढ़ती जा रही है। जनता में भाजपा और मनोहर लाल खट्टर सरकार की नाकारा छवि के बावजूद विपक्ष की छीछालेदर के चलते लोग भाजपा को वोट देने को मजबूर होंगे।

सबसे पहले इंडियन नैशनल लोकदल के सर्वेसर्वा अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री खट्टर से दिल्ली के हरियाणा भवन में मुलाकात की। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा इस दौरान मौजूद थे। तीनों ने नाश्ता किया। क्या खिचड़ी पकाई किसी को मालूम नहीं। लेकिन इसके बाद अभय की ओर से खुद ही बयान आया कि भाजपा से गठबंधन को लेकर हमारी कोई भी बातचीत खट्टर से नहीं हुई है।

सूत्रों का कहना है कि दरअसल इनके बीच एक डील हुई है। वह डील है जाट वोटों का बंटवारा। हरियाणा के ग्रामीण अंचल में नाराज जाट भाजपा के खिलाफ या तो कांग्रेस या फिर जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) को वोट दे सकते हैं। खट्टर और अभय चौटाला के बीच यह डील अशोक अरोड़ा ने कराई है। खट्टर ने अशोक अरोड़ा को पंजाबी हितों का वास्ता दिया और अशोक अरोड़ा ने व्यापक पंजाबी हितों के मद्देनजर अभय को खट्टर के साथ नाश्ते के टेबल पर बैठा दिया। अभय चौटाला की राजनीतिक को जिस तरह अजय चौटाला के लड़कों दुष्यंत और दिग्विजय ने धो डाला है, उसके बाद अभय बौखलाहट में वह हर काम करने को तैयार है जिससे जेजेपी किसी भी तरह से जाट वोटों पर एकाधिकार न जमा सके।

सूत्र बताते हैं कि इनैलो हर सीट पर

और खासतौर पर जाट बहुल इलाकों में जाट प्रत्याशी खड़ा करेगी और जमकर पैसा खर्च किया जाएगा। खट्टर ने तमाम तरह के वादे निभाने की बात अभय से कही है। भाजपा का थिंक टैंक लंबे समय से इस पर काम कर रहा था कि हरियाणा में जाट वोटों का बंटवारा कैसे कराया जाए या उसे किस तरह इधर-उधर बंटने पर मजबूर किया जाए। भाजपा थिंक टैंक ने पूरा प्लान बनाकर खट्टर को दिया। खट्टर ने उसका पूरी तरह से अनुसरण किया। नतीजा सामने है।

खट्टर और अभय चौटाला की इस डील के खतरे बहुत सारे हैं। इससे पंजाबी बनाम जाट राजनीति की लड़ाई का दौर लौटेगा। भजनलाल और चौधरी देवीलाल के समय जिस तरह इस राजनीति को हवा मिली थी, वह दौर फिर लौट सकता है। लेकिन खट्टर न तो भजनलाल हैं और न अभय चौटाला अपने दादा ताऊ देवीलाल की तरह संघर्ष से निकले नेता हैं। तो इस डील का नतीजा यह निकलेगा कि जाट और ज्यादा नाराज होकर या तो कांग्रेस की तरफ जाएगा या फिर जेजेपी की तरफ। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस के पास काफी पंजाबी लीडर हैं, वह इस डैमेज को कंट्रोल कर सकती है और साथ में उसको कुछ फीसदी जाट वोट भी मिल सकते हैं। लेकिन इस सारी डील में नुकसान जाट नेताओं और जाट मतदाताओं का होने वाला है। यह तय है कि यूपी, बिहार की तरह हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव और आगे विधानसभा चुनाव जातिवाद, बिरादरीवाद, समुदायवाद के नाम पर लड़ा जाना है।

दुष्यंत चौटाला- अरविंद केजरीवाल की जुगलबंदी

दुष्यंत और अरविंद केजरीवाल की भी चुनावी डील हुई है। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन कम से कम हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषकों के गले नहीं उतर रहा। केजरीवाल की पार्टी नवीन जयहिंद जैसे प्यादे के सहारे कई साल से सक्रिय है लेकिन हरियाणा में इस पार्टी का ढंग का संगठन तक नहीं खड़ा हो पाया है। वह शिद्दत से गठबंधन की तलाश में थी। पहले तो उसने कांग्रेस से गठबंधन के लिए हाथ-पैर चलाए। लेकिन वहां से साफ-साफ मना होने के बाद केजरीवाल ने जेजेपी की तरफ रुख किया। केजरीवाल को यह अच्छी तरह मालूम है कि वह ऐसी पार्टी के सहारे ही हरियाणा में तैर सकते हैं, जिसका कोई जनाधार हो। इसलिए उन्होंने दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाया।

यह समझ से बाहर है कि आखिर इस गठबंधन से जेजेपी को आम आदमी पार्टी से हरियाणा में क्या हासिल होगा। जेजेपी के पास जाट वोटों का बहुत बड़ा आधार है, ऐसे में उसे केजरीवाल से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर जेजेपी को यह लगता है कि शहरी इलाकों में केजरीवाल की पार्टी का आधार है तो यह उसकी भूल है। आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में किसी समुदाय विशेष का आधार नहीं है। चुनाव बाद यह साफ हो जाएगा कि केजरीवाल की पार्टी को हरियाणा में कितने फीसदी वोट मिले और जेजेपी को कितने फीसदी वोट मिले।

क्या केजरीवाल की नजर कांग्रेस और भाजपा के बागी उम्मीदवारों पर है...या फिर अगले विधानसभा चुनाव पर है। दरअसल, आम आदमी पार्टी की नजर दोनों पर है। दूसरी पार्टी के बागी नेताओं से मोटा चंदा लेकर उन्हें टिकट दे सकती है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में वह जेजेपी से ज्यादा सीटें मांग सकती है। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी दो-चार सीटें निकाल सकती है। इस तरह लोकसभा चुनाव दरअसल उसके लिए विधानसभा चुनाव की रिहर्सल है। कुल मिलाकर केजरीवाल-दुष्यंत के गठबंधन से केजरीवाल को ज्यादा फायदा है, दुष्यंत को मामूली फायदा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है।

कांग्रेसी सोए पड़े हैं...

जिस पार्टी के पास हरियाणा में नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, वह चुनाव की घोषणा के बावजूद सोई पड़ी है। कांग्रेस राज्य की किसी भी सीट पर चुनाव के लिए तैयार होती नहीं दिखाई दे रही है। एक परिवर्तन यात्रा निकालकर पार्टी को लगता है कि जनता उसे घर बैठे ही जिता देगी। तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी कम से कम एक साल से तो कर रही थीं। लेकिन कांग्रेस ने कायदे का न कोई जन आंदोलन छेड़ा और न ही राज्य की भाजपा सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर किया। बीच में तमाम ऐसे मुद्दे आए जिन पर हर जिले में कांग्रेस बड़े आंदोलन छेड़ सकती थी।

अब लोकसभा चुनाव में टिकटों का फैसला होने के बावजूद किसी भी जिले में उसकी कोई बैठक या सभा होती नजर नहीं आ रही है। फ़रीदाबाद और हिसार से नाम तय करने में जरूरत से ज्यादा देरी लगाई जा रही है। जिन सीटों पर फैसला हो चुका है, उन प्रत्याशियों से प्रचार शुरू करने को कहा ही नहीं जा रहा है। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने को तैयार है।

कृष्णपाल गूजर: टिकट मिलने का जश्न तो हो गया, 23 मई को क्या होगा ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते शनिवार स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल को लोकसभा चुनाव के लिये भाजपा का टिकट मिलने के बाद उनके सेक्टर 28 स्थित निवास पर ढोल-नगाड़ों की थाप पर रात भर जश्न मनाया गया। समर्थकों का नाचना-कूदना और शाही भोज चलता रहा। कृष्णपाल अपनी मस्ती में इतने वेसुध रहे कि उन्हें इतनी भी सुध नहीं रही कि आस-पास सैंकड़ों घरों में और भी परिवार रहते हैं। खुद तो आगामी पांच साल के लिये लूट का नया परमिट मिलने की आस में मगन थे लेकिन उनके इस शोर से पास-पड़ोस के निवासियों को कितनी परेशानी हुई, इससे सांसद महोदय को कोई सरोकार नहीं था। वैसे भी ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम के लिये बने कानून के अनुसार इस तरह के शोर-शराबे के लिये एसडीएम से परमीशन लेनी होती है और उल्लंघन करने पर पुलिस कार्यवाही करती है। परंतु यहां तो खुद 'सरकार' ही कानून का मखौल उड़ा रही थी तो बेचारी पुलिस की क्या

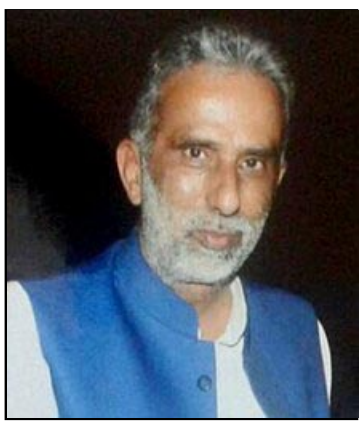

मजाल जो कुछ करने की सोचे।

संदर्भवश, समझने की बात तो यह है कि करोड़ों टिकट के लिये खर्चने के बाद करोड़ों चुनाव जीतने के लिये आखिर कोई क्यों खर्च करता है ? और फ़िर कृष्णपाल जैसा व्यक्ति जो पांच साल तक पूरे देश, प्रदेश व क्षेत्र की 'सेवा' कर चुका है उसे क्या पड़ी इतना भारी-भरकम खर्च करके

शेष पेज दो पर

तलवारें लहरा कर हिंदू सेना ने फ़ैलाया आतंक, पुलिस बनी रही तमाशबीन

गुड़गांव (म.मो.) बीते सप्ताह पहले नवरात्रे के दिन शहर में तथाकथित हिंदू सेना ने तलवारें लहराते हुए जुलूस निकाल कर मीट की दुकानों को बंद कराने के लिये आतंक का माहौल बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ-साथ विभिन्न टीवी चैनलों ने भी इसको दिखाया। सैंकड़ों लोगों के जुलूस में से केवल दो को गिरफ़्तार कर मानो पुलिस ने बहुत बड़ा काम कर दिया। पुलिस ने जनता पर एक और 'अहसान' यह भी किया कि किसी नागरिक द्वारा थाने में आकर शिकायत दर्ज न कराने के बावजूद उसने स्वत: मुकदमा दर्ज करके इतनी बड़ी कार्यवाही कर दिखाई।

किसी भी नागरिक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज न कराने से स्पष्ट है कि इस नाकारा पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं, फ़िर थाने में जाकर कोई क्यों जिल्लत उठाये ? विदित है कि शहर में 60 से अधिक थाने चौकियां हैं और हर चौक-चौराहे पर पीसीआर जिप्सी के अलावा ट्रैफ़िक पुलिस भी तैनात रहती है। जब पुलिस खुद सब कुछ देख रही है तो कोई क्या शिकायत दर्ज कराये। सोते को तो जगाया जा सकता है, जागते को कोई क्या जगाये ?

पुलिस ने बेशक मुकदमा दर्ज करके अपने

गुड़गांव में मांस की दुकानें बंद कराने के दौरान तलवारें लहराते हिंदू सेना के गुंडे

कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली, परन्तु इस मामले में होना जाना क्या है ? कुछ भी नहीं। सरकार व पुलिस सब हिन्दू सेना की ही तो हैं। इसी लिये कोई शिकायतकर्ता बनना भी नहीं चाहता। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू सेना के नाम पर यह कोई पहली आतंक फ़ैलाने वाली कार्यवाही है। इस तरह की नौटंकी, हिंदू सेना के नाम पर कुछ लफ़ंटर यदा-कदा करते रहे हैं। एक बार तो एक बनी-बनाई शादी तुड़वाने के लिये गुंडागर्दी पर उतर आये थे ये लोग।

जहां तक सवाल है मीट की दुकानें बंद करवाने का तो जिन 109 दुकानों को नगर निगम ने बाकायदा लाइसेंस दे रखा है, उनकी सुरक्षा का पूरा दायित्व पुलिस एवं प्रशासन पर है। उन्हें कोई भी धर्म के नाम पर धमकी देकर बंद नहीं करा सकता। इनके अतिरिक्त जो सैंकड़ों दुकानें बिना लाइसेंस के जहां-तहां गली-मुहल्लों में अवैध रूप से, निगम के भ्रष्ट अफ़सरों ने खुलवा रखी हैं, उन्हें खुलने ही नहीं देना चाहिये। इसके लिये पूरी तरह से निगम व ज़िला प्रशासन उत्तरदायी है। ऐसे रिश्वतखोर अफ़सरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये, क्योंकि इन्हीं अवैध दुकानों के बहाने तथाकथित हिन्दू सेनानियों को तलवारें लहराने का मौका मिल जाता है।